ment generated at the district and village levels are maintained at the Government of India level.

To give adequate coverage to women under employment generation, 30 per cent employment opportunities under JRY have been earmarked for women. However, to some extent, due to social taboos or preference of a family to send male member for manual work, the required number of women workers do not report for JRY works in some States.

नई पंचायती राज प्रणाली के अधीन चुनाव

7091. **श्री रामजी लाल :**
श्री येरा नारायणा वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिये संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के बाद छः माह की अवधि के भीतर पंचायती राज निकायों के चुनाव कराना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को अपने-अपने राज्य के पंचायत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नयी पंचायत प्रणाली (त्रि-स्तरीय) के लिये सभी राज्यों में चुनाव कराने की सलाह दी है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में नयी पंचायत प्रणाली स्थापित कर दी गई है ;

(घ) किन-किन राज्यों में यह प्रणाली अब तक स्थापित नहीं की गई है ;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(छ) पंचायत चुनाव कराने के लिये हरियाणा राज्य को वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पंचायती राज के संबंध में राज्य कानून बनाये जाने के पश्चात् धारा 243 बी (1), 243ई (3) तथा 243(4) के साथ पठित राज्य अधिनियम में इस आशय हेतु किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा सकते हैं ।

(ख) भारत सरकार ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि पंचायती राज कानूनों में परिवर्तन करने के पश्चात राज्यों को जहां कहीं चुनाव कराये जाने अपेक्षित हैं, वहां पर चुनाव कराने होंगे ।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों ने अपने राज्य अधिनियमों को संविधान (173वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरुप बनाने के लिये कानून बना लिये हैं, जिसके पश्चात् राज्यों द्वारा तदनुसार आगे कदम उठाये जायेंगे ।

(च) और (छ) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इस प्रयोजन हेतु राज्यों को निधियां स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार की कोई योजना नहीं है ।

JRY Gran's in Andhra Pradesh

7092. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government reduced J.R.Y. grants to Andhra Pradesh;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether the Andhra Pradesh Government has directed the J.R.Y. fund, to other purposes;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL

DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such instance has come to our notice.

Distribution of funds by CAPART

7093. SHRI V. GOPALSAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how much funds were disbursed by CAPART to various projects in each State during the last three years, State wise and year-wise;

(to) whether it is a fact that Government have not released funds to CAPART this financial year so far to be released to agencies/societies executing various project*;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) when Government would release funds so that projects do not come to halt;

(e) how many cases are pending presently for release of funds; and

(f) what steps are being taken to revamp CAPART administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The State-wise details of number of projects sanctioned, number of Non-Governmental Organisations (NGOs) assisted, amount sanctioned and amount released during the last three years by Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) for rural development works are at Annexure *[See* Appendix 170 Annexure No. 143.]

(b) to (e) During the current financial ear 1994-95, an amount of Rs. 19.01 Crores has been released to CAPART. Further releases will be made as per the prescribed procedure.

(f) The working of CAPART is reviewed from time to time in the meetings of the Executive Committee & General Body of CAPART and, whenever considered necessary, suitable steps are taken to improve its working. This is a continuous process.

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

7094. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु क्या-क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 के लिये उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ग) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संबंधी उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कम लागत वाले परिवारिक शौचालयों, महिलाओं के लिये ग्राम परिसरों और अन्य स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है ।